सनरेफ इंडिया हाउसिंग प्रोग्राम - हरित आवास पर लोकसंपर्क कार्यक्रम

राष्ट्रीय आवास बैंक और फ्रांस विकास एजेंसी ने हरित किफायती आवास के लिए प्रतिस्पर्धी निधियन को बढ़ावा दिया

कोलकाता, 10 दिसंबर, 2021: भारत के शीर्ष आवास वित्त संस्थान, राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), फ्रांस विकास एजेंसी (एएफडी), और यूरोपीय संघ (ईयू) ने आज 'सनरेफ इंडिया हाउसिंग प्रोग्राम' के माध्यम से हरित और किफायती आवास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों के आबंटन के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई।

एएफडी से €100 मिलियन की ऋण व्यवस्था द्वारा समर्थित यह कार्यक्रम बैंकों, आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) और घर खरीदारों को हरित तथा किफायती आवास परियोजनाओं एवं इससे संबद्ध निवेशों के निधियन हेतु सक्षम बनाता है।

इस पहल के एक भाग के रूप में, हरित किफायती आवास की महत्ता को उजागर करने के लिए कोलकाता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बैंकों, आ.वि.कं., रियल एस्टेट डेवलपर्स, सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ हरित-बिल्डिंग विशेषज्ञ, आर्किटेक्ट और हरित सामग्री उत्पादकों ने भाग लिया। राष्ट्रीय आवास बैंक और फ्रांस विकास एजेंसी के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में हरित आवास के कई लाभों - पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक - को रेखांकित किया।

राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री राहुल भावे ने अपने सम्बोधन में कहा, "सनरेफ इंडिया हाउसिंग प्रोग्राम के रियायती वित्त पोषण और हरित आवास की दिशा में अन्य क्षमता निर्माण की पहलों से आवास के क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल रणनीतियों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग में वृद्धि आएगी। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ से €12 मिलियन का अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसमें भारत में कार्यक्रम के प्रचार के लिए €3 मिलियन का तकनीकी सहायता अनुदान एवं परियोजना विकासकों द्वारा ग्रीन लेबल प्रमाणन पर होने वाले व्यय का समर्थन करने के लिए €1 मिलियन शामिल है"।

सनरेफ इंडिया हाउसिंग प्रोग्राम पेरिस समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धता, विकासशील देशों में COP26 के दौरान बनी सर्वसम्मति से जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के लिए और कम कार्बन-उत्सर्जन मार्ग की दिशा में काम करने के लिए यूरोपीय संघ की वैश्विक प्राथमिकताओं के अनुरूप है।

इस संदर्भ में, किफायती हरित आवास एक स्तर जोड़ता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भवन अपने पूरे जीवन चक्र में पर्यावरण के अनुकूल और संसाधन-कुशल बने रहें। वास्तव में, आवास क्षेत्र में कृषि, ऊर्जा और परिवहन जैसे अन्य प्रमुख उत्सर्जक क्षेत्रों की तुलना में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाने की अपार संभावनाएं हैं।

एलीसी पोर्नेट, प्रमुख - ऊर्जा और जलवायु वित्त, एएफडी, ने कहा कि "निर्माण क्षेत्र ऊर्जा का एक प्रमुख उपभोक्ता है, एवं इसका जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरण पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अत: हरित दृष्टिकोण के एकीकरण के साथ, नए विकास कार्यक्रमों को एक अलग दृष्टिकोण से आरम्भ करने की बहुत बड़ी संभावना है।"

रिकॉर्ड के लिए, वर्ष 2025 तक, सनरेफ इंडिया हाउसिंग प्रोग्राम से 4,200 परिवारों को लाभ होगा, जिनमें से कम से कम आधे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होंगे।

श्री विशाल गोयल, महाप्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक ने कहा कि कोलकाता में इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शहर में पिछले कुछ वर्षों में ग्रीन-रेटेड आवासीय भवनों में तेजी से वृद्धि हुई है।

श्री विक्रम देव, सहायक महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।